इस मामले में याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए, हम मानते हैं कि हमारे समक्ष एल-14 लाइसेंस रखने वाले याचिकाकर्ता भी उसी राहत के हकदार हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य में उनके समकक्षों को दी जा रही है।

(14) उपरोक्त कारणों से, हम इन याचिकाओं को स्वीकार करते हैं और प्रतिवादियों को धारा की उप-धारा (1) के खंड (ए) के प्रावधान के मद्देनजर एल-13 लाइसेंसधारियों से आयकर नहीं काटने/चार्ज न करने का निर्देश देने वाली निषेधाज्ञा जारी करते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 44 एसी; और परिपत्र, दिनांक 26 जून, 1989, अनुबंध पी-1 को लागू करना। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे एल-14 लाइसेंस रखने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा देय उत्पाद शुल्क पर आयकर न लगाएं/कटौती न करें। कोई लागत नहीं.

(15) 1990 का सिविल विविध.संख्या 39 और 1989 का 20983, सीडब्ल्यूपी 1989 का 7161 में तदनुसार निस्तारित किया जातें हैं।

आरएनआर

न्यायमूर्तिगण आई.एस. तिवाना और जी.आर. *मजीठिया के समक्ष*

पंजाब वित्तीय निगम, चंडीगढ़, - याचिकाकर्ता।

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ व अन्य, - प्रतिवादिगण ।

1985 की *संशोधित सिविल रिट याचिका संख्या 2584*

7 जून 1990.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947—एस.एस. 2(ए)(ii) और 10- *औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम,* 1957- *आरएल 2(एफ) - भारत का संविधान,* 1950- अनुच्छेद 239— *सामान्य खण्ड अधिनियम (* 1897 का एक्स)—धारा. 3(60) *और* 8(बी) *(iii)-पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (* 1966 *का* 31) *-धारा* 4 *और* 88- *चंडीगढ़ (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम,* 1987 (1988 का 2)- धारा. 4- *औद्योगिक संदर्भ- केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में उत्पन्न होने वाले विवादों को संदर्भित करने का क्षेत्राधिकार- उपयुक्त सरकार- एक केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उपयुक्त सरकार है केंद्र सरकार - जहां उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के संदर्भ को यूटी के प्रशासक के संदर्भ के रूप में माना जाएगा - यूटी के प्रशासक औद्योगिक विवाद को संदर्भित करने के लिए सक्षम हैं - संदर्भ प्रशासक के नाम पर व्यक्त किया गया है लेकिन अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है उप-प्रतिनिधिमंडल को - चंडीगढ़ (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से बचाई गई शक्ति का ऐसा प्रयोग - पूर्वव्यापी बचत विधायी क्षमता के अंतर्गत है।*

माना गया कि चंडीगढ़ की क्षेत्रीय सीमा के भीतर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत इन औद्योगिक संदर्भों के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार थी और सामान्य धारा 8 (बी) (iii) के मद्देनजर धारा अधिनियम के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को केंद्र सरकार माना जाएगा यदि उसकी कार्रवाई उसे दिए गए अधिकार के भीतर थी।

(पैरा 3)

अभिनिर्धारित किया कि हालांकि विवादित संदर्भ मुख्य आयुक्त/प्रशासक, चंडीगढ़ के नाम से व्यक्त किए गए हैं, फिर भी उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन के एक या दूसरे सचिव द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित किया गया है। नवीनतम वैधानिक प्रावधानों, यानी, 1988 के अधिनियम संख्या 2, के मद्देनजर उप-प्रतिनिधिमंडल के रूप में चुनौती पर किसी भी गहन विचार की आवश्यकता नहीं है। चंडीगढ़ (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी शक्ति, प्राधिकरण या क्षेत्राधिकार

या कोई भी कर्तव्य जो प्रशासक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में लागू किसी भी कानून के तहत प्रयोग या निर्वहन कर सकता है, ऐसे अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है जो केंद्र सरकार या प्रशासक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है। आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना. इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 4 प्रशासक द्वारा ऐसी शक्तियों के सभी पहले प्रयोग या कर्तव्यों के प्रदर्शन को मान्य करती है।

(पैरा 5)

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चंडीगढ़ (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 की धारा 4 में उल्लिखित कोई भी शक्ति या अधिकार किसी भी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रदान नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, वे यह दिखाने के लिए किसी मिसाल या सिद्धांत का उल्लेख करने की स्थिति में नहीं हैं कि यह पूर्वव्यापीता विधायिका यानी संसद के विशेषाधिकार से परे कैसे है।

(पैरा 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका *में प्रार्थना की गई है कि* :-

(i) *एए प्रमाण पत्र की प्रकृति* सी के संदर्भ *में संदर्भ अनुलग्नक* पी/2 को रद्द करने के लिए क्यू जारी *किया जाना चाहिए ;*

(ii) *किसी भी रिट, निर्देश या आदेश के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट, जिसमें पुरस्कार अनुबंध* पी/3 को *उस सीमा तक रद्द कर दिया जाता है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या* 3 *को बिना किसी पिछले वेतन के सेवा की निरंतरता के साथ फिर से बताए जाने का आदेश दिया गया है ;*

(iii) *कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उपयुक्त समझे, कृपया जारी किया जा सकता है;*

(iv) *मामले के रिकॉर्ड तलब किए जाएं;*

(v) *प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस जारी करने की कृपा की जा सकती है;*

(vi) पी/एल *से* पी/3 *की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जाए;*

(v) *याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए।*

आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अवार्ड अनुबंध पी/3 के संचालन *पर रोक लगाई जाए।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. मोंगिया के साथ अधिवक्ता जे.एस. साठी।

प्रतिवादीगण संख्या 1 *और* 2 के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक भान, अधिवक्ता आर.के. गर्ग के साथ।

प्रतिवादी संख्या 3 के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जे.सी. वर्मा, दिनेश कुमार, अधिवक्ता के साथ ।

निर्णय

1. न्यायमूर्ति एस. *तिवाना,*

(1) सामान्य प्रश्न जो 1985 की इन 24 सिविल रिट याचिकाओं संख्या 2584 से 2586, 3017, 3185, 3214, 3215, 3774, 3853 और 4017 में बड़ा है; 1278, 2192, 3373, 3417, 3456, 4027, 4042, 4048, 6296, 1986 के 6600 से 6602; 1987 का 265 और 1986 का 4402, में समान है, संघ के मुख्य आयुक्त/प्रशासक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 10(एल)(सी) के

तहत किए गए संबंधित संदर्भों की वैधता से संबंधित है। क्षेत्र, चंडीगढ़. यह सर्वमान्य है कि अधिनियम की धारा 2(ए)(ii) के साथ पठित धारा 10 के संदर्भ में इन संदर्भों को बनाने के लिए उपयुक्त सरकार राज्य सरकार है। याचिकाकर्ताओं का रुख यह है कि. संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक राज्य सरकार के कार्यों को अपने ऊपर नहीं ले सकता है। उनके विद्वान वकील के अनुसार ऐसा तब और अधिक होता है , *जब उन्होंने* अधिसूचना संख्या एसओ 3269, दिनांक 1 नवंबर, 1966 (कॉपी अनुलग्नक आरएल/1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे गए प्राधिकरण या अधिकार के भीतर कार्य नहीं किया है। दूसरी ओर, प्रतिवादी प्राधिकारियों की दलील यह है कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3(60) के अनुसार, किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में राज्य सरकार

केंद्र सरकार है और किसी भी कानून के तहत प्रयोज्य राज्य सरकार की सभी शक्तियां, चाहे वह केंद्रीय अधिनियम हो या राज्य अधिनियम, केंद्र सरकार द्वारा प्रयोज्य हो जाती हैं और प्रशासक उत्तरार्द्ध का प्रतिनिधि होने के नाते, कर सकता है। वैध रूप से वही अभ्यास करें। हालांकि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3(60) और औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 के नियम 2(एफ) के आलोक में, जैसा कि अधिनियम के तहत बनाया गया है, विवादित संदर्भों को सुरक्षित रूप से सख्ती से कानूनी माना जा सकता है। और वैध है, फिर भी बहस के रूप में परस्पर जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, संवैधानिक और विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का संदर्भ उस हद तक आवश्यक है जहां तक ये प्रासंगिक हैं।

(2) यह विवाद से परे है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के लागू होने के साथ 1 नवंबर, 1966 को अस्तित्व में आया। उसी की धारा 4 के अनुसार इसे प्रदेशों से अलग कर दिया गया था। भूतपूर्व पंजाब राज्य के. इस अधिनियम की धारा 88 में यह प्रावधान है कि भाग 2 के प्रावधान जिसमें ऊपर उल्लिखित धारा 4 भी शामिल है, उन क्षेत्रों में किसी भी परिवर्तन को प्रभावित नहीं माना जाएगा जहां नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई कानून विस्तारित या लागू किया गया है और क्षेत्रीय पंजाब राज्य के लिए ऐसे किसी भी कानून के संदर्भ में, जब तक अन्यथा एक सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी को खिलौना प्रदान नहीं किया जाता है, नियत दिन से ठीक पहले, यानी 1 नवंबर, 1986 से ठीक पहले उस राज्य के भीतर के क्षेत्रों के अर्थ के रूप में समझा जाएगा। अनुच्छेद 239 संविधान, जो एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है, यह बताता है कि संसद द्वारा कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रशासक के माध्यम से, उस सीमा तक प्रशासित किया जाएगा, जब तक वह उचित समझे। उनके द्वारा ऐसे पदनाम के साथ जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकते हैं। प्रशासक/मुख्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करते हुए की जाती है। इस संबंध में, ऊपर उल्लिखित केंद्र सरकार की अधिसूचना, अनुलग्नक आरएल/1, पढ़ती है निम्नलिखित नुसार: -

> "गृह मंत्रालय
>
> नई दिल्ली, 1 नवंबर, 1966. एस.ओ. 3269.-जबकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1986 का 31) की धारा 4 के तहत, उसमें निर्दिष्ट क्षेत्र 1 नवंबर, 1966 से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। .
>
> और जबकि उक्त अधिनियम के धारा 88 के तहत, उक्त अधिनियम के भाग -11 के प्रावधानों को उन क्षेत्रों में किसी भी बदलाव के लिए प्रभावी नहीं माना जाएगा, जिन पर 1 *नवंबर 1966 से ठीक पहले लागू कोई भी कानून* लागू होता है, और ऐसे किसी भी कानून में पंजाब राज्य के क्षेत्रीय संदर्भों को, जब तक कि सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, उक्त दिन से ठीक पहले उस राज्य के भीतर के क्षेत्रों के अर्थ के रूप में समझा जाएगा:
>
> उपरोक्त किसी भी कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां अब केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं;

> अब, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (i) और इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों के अनुसरण में, राष्ट्रपति निर्देश देते हैं कि, उनके नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक चंडीगढ़, उक्त क्षेत्र के संबंध में, 1 नवंबर, 1966 से ऐसे किसी भी कानून के तहत राज्य सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा। (जोर दिया गया)।

जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि न तो भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि या प्रतिनिधि के रूप में प्रशासक को राज्य सरकार के रूप में स्टाइल किया जा सकता है और न ही उपर्युक्त अधिसूचना अनुलग्नक आरएल/1 उन्हें इसके तहत किसी भी कर्तव्य को पूरा करने के लिए कोई अधिकार देता है। अधिनियम, क्योंकि उनके विद्वान वकील के अनुसार, वह केवल उन कानूनों के अनुसरण में राज्य सरकार के रूप में कार्य कर सकते हैं जिनके प्रावधान पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 4 के संचालन से प्रभावित हुए थे। दूसरे शब्दों में, अधिनियम का संचालन इस क्षेत्र में, यानी, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, 1966 अधिनियम के प्रवर्तन से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है। तर्क यह है कि यह अधिनियम अपने बल के आधार पर तत्कालीन पंजाब राज्य पर लागू होता था और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के गठन के बाद भी लागू होता रहा।

(3) जहां तक की मामले के पहले पहलू का प्रश्न है जिस पर विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता द्वारा प्रकाश डाला गया, वही, मेरे विचार से, सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम निर्णय, जो की गोवा *सैंपलिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन* बनाम *जनरल सुपरिंटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया प्रा. और अन्य* (1) *के नाम से रिपोर्टेड है, द्वारा उत्तर दिया गया है।*

इस तर्क की जांच करते हुए कि केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कोई राज्य सरकार नहीं है और केंद्र सरकार , यदि बिल्कुल भी कहा जा सकता है, 'एकमात्र सरकार है और राज्य सरकार की अनुपस्थिति में, केंद्र सरकार होगी राज्य सरकार की सभी शक्तियां भी उसके पास हैं, और इसलिए, केंद्र सरकार संदर्भ देने के उद्देश्य से उपयुक्त सरकार होगी, संविधान के विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, उनके आधिपत्य ने प्रश्न उठाया: "क्या यह संवैधानिक रूप से होगा किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को राज्य सरकार के रूप में वर्णित करना सही है? और इसका उत्तर इस प्रकार दिया। यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राज्य सरकार की अवधारणा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए विदेशी है और अनुच्छेद 239 में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना है। राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य कर सकता है। प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। उनकी स्थिति किसी राज्य के राज्यपाल से बिल्कुल अलग है। इसलिए, किसी भी स्थिति में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्य सरकार के विवरण के लिए योग्य नहीं है। *जहां भी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में "राज्य सरकार" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार होगी।* अतः केन्द्र सरकार ही उपयुक्त सरकार है। 1957 के नियम 2 के खंड (एफ) अधिनियम के तहत बनाए गए नियम मामले को विवाद के दायरे से परे ले जाते हैं जब यह केंद्र शासित प्रदेश में एक औद्योगिक विवाद के संबंध में कहता है जिसके लिए उपयुक्त सरकार केंद्र सरकार है, केंद्र का संदर्भ सरकार या भारत सरकार को क्षेत्र के प्रशासक के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इन संदर्भों के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार थी और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 8 (बी) (iii) के मद्देनजर, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को ही राज्य सरकार माना जाना चाहिए। केंद्र सरकार यदि उसकी कार्रवाई अन्यथा उसे दिए गए अधिकार के भीतर थी।

(4) याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई दलील का दूसरा पहलू कि प्रशासक ने अधिसूचित अपने प्राधिकरण के भीतर कार्य नहीं किया है, - अनुबंध आरएल/1 *के अनुसार ,* **गुणहीन** *प्रतीत होता है।*

(1) एआईआर 1985 एससी 357,

'किसी भी कानून' शब्द के दायरे को किसी राज्य कानून या राज्य अधिनियम तक कम करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका अर्थ केंद्रीय अधिनियमों को बाहर करना है। 'किसी भी कानून' का तात्पर्य अनिवार्य रूप से सभी राज्य और केंद्रीय अधिनियमों से होगा। इस अधिसूचना का एकमात्र निहितार्थ यह है कि किसी भी कानून के तहत सभी शक्तियां और कार्य (जैसा कि अधिसूचना के पहले भाग में उपयोग किया गया है) अब से, यानी, इस अधिसूचना के जारी होने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा किया जाएगा। अधिसूचना के उत्तरार्ध में अभिव्यक्ति 'ऐसा कोई कानून' केवल उस कानून को संदर्भित करता है जिसके तहत प्रशासक कार्य करता है या कार्य करने वाला होता है।

(5) एक स्तर पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इनमें से अधिकांश मामलों में हालांकि विवादित संदर्भ मुख्य आयुक्त/प्रशासक, चंडीगढ़ के नाम पर व्यक्त किए गए हैं, फिर भी उन पर किसी न किसी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं या प्रमाणित किए गए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन के सचिव और, इसलिए, इसे वैध रूप से बनाया गया नहीं माना जा सकता है। विद्वान वकील की इस प्रस्तुति को नवीनतम वैधानिक प्रावधानों, यानी, 1988 के अधिनियम संख्या 2, चंडीगढ़ (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 के मद्देनजर किसी भी गहन विचार की आवश्यकता नहीं है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी शक्ति, प्राधिकरण या क्षेत्राधिकार या कोई भी कर्तव्य जिसका प्रशासक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में लागू किसी कानून के तहत प्रयोग या निर्वहन कर सकता है, उसका प्रयोग या निर्वहन ऐसे अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जो केंद्र सरकार या प्रशासक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है। सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा. इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 4 प्रशासक द्वारा ऐसी शक्तियों के सभी पहले प्रयोग या कर्तव्यों के प्रदर्शन को मान्य करती है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

> "किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विपरीत, जिसके तहत कोई भी शक्ति, प्राधिकार या अधिकार क्षेत्र या कोई कर्तव्य जो प्रशासक चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश में लागू किसी भी कानून के तहत प्रयोग या निर्वहन कर सकता है । इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी अधिकारी या

अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया गया है, ऐसी शक्ति, अधिकार, क्षेत्राधिकार या कर्तव्य को ऐसे अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा वैधता और प्रभावी ढंग से प्रयोग या निर्वहन माना जाएगा जैसे कि उप- धारा 3 की धारा (1) सभी भौतिक समयों पर लागू थी जब ऐसी शक्ति, प्राधिकार या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया गया था या ऐसे कर्तव्य का निर्वहन किया गया था और उस अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को एक अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया था

> या उक्त उपधारा के तहत केंद्र सरकार या प्रशासक द्वारा उस संबंध में अन्य प्राधिकारी, और तदनुसार, कोई भी मुकदमा या अन्य कार्यवाही किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण में या अन्य प्राधिकारी के समक्ष इस आधार पर शुरू या जारी नहीं रखी जाएगी कि ऐसा अधिकारी या अन्य प्राधिकारी ऐसी शक्ति, अधिकार या क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने या ऐसे कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम नहीं था।

कोई भी विद्वान वकील यह बताने में सक्षम नहीं है कि किसी भी विवादित संदर्भ को किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिसे ऐसे संदर्भों को प्रमाणित करने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

(6) फिर भी इन विद्वान वकीलों द्वारा उनके धनुष में दूसरी डोर जोड़ने के लिए उठाया गया एक और कमज़ोर तर्क यह है कि उपरोक्त क़ानून में उल्लिखित कोई भी शक्ति या अधिकार किसी भी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रदान नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, वे यह दिखाने के लिए किसी मिसाल या सिद्धांत का उल्लेख करने की स्थिति में नहीं हैं कि यह 'पूर्वव्यापीता' विधायिका, यानी संसद के विशेषाधिकार से परे कैसे है।

(7) पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई है।

(8) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से मैं इन सभी याचिकाओं को योग्यता से रहित पाता हूं और उन्हें रुपये 1000 खर्चा, प्रत्येक, जो मैंने निर्धारित किया है, के साथ ख़ारिज करता हूँ।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरूग्राम, हरियाणा